श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: सर, इसमें कोई एक घंटे, आधे घंटे की बात हो जाए, तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति: हां, हो जाएगी। अगले सेशन में बहस हो जाएगी।

Central University in Bodoland Area

*742. SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to set up a Central University in Assam, particularly in the Bodoland area;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) The tripartite peace talks involving the representatives of the Central Government, Government of Assam and Bodo Liberation Tiger are continuing to find a lasting peaceful solution of the Bodo issues, which include, *inter-alia* setting up of Centrally funded educational institutions in Bodoland area.

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: Sir, I have seen the reply given by the hon. Minister, but I am not satisfied with the answer. The answer is incomplete. My question was relating to the Government's plan for swetting up a Central University in the Bodoland area of Assam, but the answer given by the hon. Minister is about setting up Centrally-funded educational institutions. What is a Centrally-funded education institution? What does it mean? I fail to understand the meaning of it. The hon. Minister has mentioned about the peace negotiations going on with an extremist outfit, the Bodo Liberation Tigers. Presently, the negotiations are going on. But, during the peace negotiations, I remember, the Government of India had committed to set up of a Central University in Assam, particularly, in the Bodoland area. That was the commitment made by the Central Government, and the decision was also endorsed by the State Government of Assam. It has now become a public commitment. Then, why is the Government trying to retreat from its original commitment?

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: This is my first question. The

second question is: While the State Government has endorsed the decision, what are the reasons for not setting up a Central University in the Bodoland area? Can the hon. Minister give me the reasons as to why a Central University cannot be set up in that area? This is my second question.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, जो वस्तुस्थिति थी वह मैंने सामने रखी है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और बोडो प्रतिनिधियों से वार्ता नाजुक दौर में है। उस वार्ता का परिणाम निकलने दीजिए, उसमें क्या-क्या चीजें अंतिम रूप में तय होती हैं, जो कुछ भी तय होंगी, उसे हम पूरा करेंगे। केन्द्र सरकार, बोडो प्रतिनिधि और राज्य सरकार मिलकर उसमें कुछ तय करेंगे, निर्णय होगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है और वार्ता बहुत संवेदनशील दौर में है, मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर क्योंकि यह बहुत ही सेन्सटिव मामला है, एक क्षेत्र में शांति स्थापना का और वहां के जनजाति लोगों के साथ मिलकर एक व्यवस्था उत्पन्न करने का है तो इसमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसमें जो फैसला होगा, वह पूरा किया जाएगा।

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: Sir, I want to make a submission before the hon. Minister. It concerns the sentiments of the people living in that area. Therefore, I request and urge upon the hon. Minister to reconsider the demand for setting up of Central University in the Bodoland area. That was the decision of the Government. Why are they going back on it? This is my last question.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, मैंने जैसे कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, लेकिन राज्य सरकार और बोडो प्रतिनिधि भी उसके दो अन्य पक्ष हैं, राज्य सरकार तो एक महत्वपूर्ण पक्ष है और अभी जो वहां नई सरकार बनी है उसके साथ भी वार्ता चल रही है, वह भी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। जो भी वहां बोडो समस्या के समाधान के लिए निर्णय होंगे और जो हमारे मंत्रालय से संबंधित होंगे, उन्हें हम पूरा करेंगे। यह केवल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है, उसमें मेडीकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नीकल कॉलेज, यह सब चीजें शामिल हैं और इसलिए यह 'सेंट्रली फंडेड' शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें जो भी तय होंगे वह हम अवश्य पूरा करेंगे।

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब यह निर्णय अपकी त्रिपक्षीय वार्ता में हुआ है और आपने यह कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है, प्रश्न वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का, इंजीनियरिंग कालेज खोलने का, मेडिकल कालेज खोलने का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस संवेदनशील मामले में बिना किसी विलम्ब के–क्योंकि यह मामला संवेदनशील है, असम में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, बोडोलैंड की बात आपके सामने आई है–केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे

में, यह तो बोडोलैंड का मामला है, आपके मंत्रालय ने कोई नीति निर्धारित की है, न केवल असम के मामले में बल्कि अन्य स्थानों पर भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में आपकी कोई नीति है और यदि है तो उस नीति में राज्य सरकार का और केन्द्र सरकार का कितना-कितना योगदान होगा और उसमें क्या प्रगति होगी? प्रश्न आज केवल इस बात का है कि वहां पर शांति की स्थापना हो, तो वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की जो काफी समय से मांग चली आ रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इस संवेदनशील मामले में क्या संवेदनशील मंत्री महोदय विचार करके कोई निर्णय शीघ्र लेंगे?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अतिसंवेदनशील माननीय सदस्य ने एक संवेदनशील प्रश्न पर अपने विचार रखे हैं। वे एक बहुत ही सुलझे हुए प्रशासक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे है, इसलिए वे जानते हैं कि ऐसे मामलों में किस प्रकार से निर्णय होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वे इसकी अतिसंवेदनशीलता को समझते हुए इस बात पर पूरे आश्वस्त रहें कि जो कुछ भी फैसला होगा, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। ...(**व्यवधान**)... वह जो जिम्मेदारी है, वह गृह मंत्रालय के पास है, मेरे मंत्रालय के पास नहीं है।

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय सभापति जी, हर मंत्री अपनी जिम्मेदारी को किसी न किसी मंत्रालय पर सौंप देता है। उमा भारती जी ने, इतनी असहाय मंत्री हैं ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: एक मिनट, कृपया मुझे क्षमा करेंगे। बातचीत की नोडल एजेंसी इसमें गृह मंत्रालय है और मामला संवेदनशील है। जब वहां तय हो जाएगा, जैसी राय बनेगी, वैसे हम करेंगे। किसी चीज में अनावश्यक हस्तक्षेप हमारा मंत्रालय नहीं करता। कृपया सावधान रहें, यह कोई जिम्मेदारी टालने की बात नहीं है।

श्री मोतीलाल वोरा: मुझे यह नहीं कहना है, मैं माननीय मंत्री जी से भली-भांति परिचित हूं। माननीय मंत्री महोदय कितने असहाय हैं, माननीय उमा भारती जी का प्रश्न तो निकल गया लेकिन उन्होंने कहा कि यह मामला गृह ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह उचित नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। ...(व्यवधान)...

श्री मोतीलाल वोरा: कितने असहाय मंत्री हैं, कि अपने विभाग की हर जिम्मेदारी किसी न किसी विभाग/मंत्रालय पर सौंप देते हैं। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: यह बिल्कुल गलत बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: असहायता कहां है? आपको असहायता कहां से दीख रही है? ...(व्यवधान)...

श्री मोतीलाल वोरा: मैंने तो मंत्री जी से पूछा, मैंने तो सभापति महोदय से कहा ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: असहाय तो आपकी सरकार है वहां पर।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, we have listened to what the hon. Minister has stated about the continuation of peace negotiations. I don't feel that the continuation of the peace negotiations would be a bar on going in for development activities. Setting up a University is very important, considering the unemployment and the level of education in those areas. I hope the hon. Minister would kindly take up the issue with the Ministry of Home Affairs so that the setting up of the University and the peace negotiations can continue simultaneously. We should not wait for the conclusion of the peace negotiations; and, after five years or so, we go in for the setting up of the University.

The second part of my question is, the hon. Minister has mentioned that a number of educational institutions are going to be set up in the Bodoland areas. I would like to know specifically from the hon. Minister, which are the other institutions that the Government is proposing to establish in those areas.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, मैंने पहले ही अनुरोध किया है कि इस मामले में एक पैकेज डील होती है, जब भी कभी ऐसी ट्राइपरटाइट वार्ता होती है, त्रिपक्षीय वार्ता होती है, उसमें सब इस बारे में मिलकर आते हैं कि कैसे, क्या-क्या चीजें, कब और कहां होनी चाहिए। उन सब बातों पर विचार करके जो अंतिम फैसले होंगे, उनका विधिवत् पालन किया जाएगा। मैंने उल्लेख किया कि बहुत सारी मांगें हैं--एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी वहां मांग है, मेडिकल कॉलेज की भी वहां मांग है, टैक्निकल इंस्टिट्यूशन की भी वहां मांग है, इन सब बातों पर वे विचार कर रहे हैं कि क्या चीज, कब और कहां होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, अंतिम रूप में जो तय होगा, उसका हम पालन करेंगे। बातचीत बहुत नाजुक दौर में है, जो उसमें फैसले होंगे, वही मैं करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इस सैंसेटिव मामले को, जिसमें एक विशेष क्षेत्र में शांति स्थापना की बात और वर्षों से चलते हुए एक प्रकरण को सुलझाने की बात है, इसमें थोड़ा धैर्य से काम लेने की जरूरत है। मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि आप सब इसमें सहायता करें न कि इस बात का उद्देश्य रखें कि हमने सदन के अंदर यह मांग रख दी। ऐसे मामलों में, जहां शांति स्थापना का सवाल हो, राजनीतिक उद्देश्य से प्रश्न नहीं होने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप इसमें हमारी सहायता करें, राज्य सरकार की सहायता करें, जिससे मामला जल्दी सुलझे।

SHRI DRUPAD BOROGOHAIN: Sir, there are so many sentimental problems in Assam. These problems relate to tribals and ethnic groups. Most of the problems there are sentimental problems. That is a fact. The Central Government should try to solve these problems and deal with these problems properly. I would like to make a suggestion to the hon. Minister and then put my question. Assam has a large number of tribal ethnic groups. These groups are Bodo, Rabha, Tiwa, Miching, Devri, Kachari, *i.e.* Thengal, Sonowal, Karbi, Dimacha, Kacharis. These are the main tribal groups. Several of these ethnic groups have their own languages which need to be developed. These group have their own languages and culture. To develop their languages and culture and to impart higher education through their mothertongue, the Tejpur Central University can be utilised fully. The Assam Central University can also be utilised for this purpose. I am in favour of a Central University at Kokarjhar. There are two other universities which can be utilised for the development of the culture, languages and other things of the tribal groups. I would like to know from the hon. Minister whether they have got such a proposal. I would also like to know whether your Ministry will think over it and try to solve these problems.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, अगर कोई भी विश्वविद्यालय अपने परिक्षेत्र में किसी भाषा के विकास के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाता है, कोई स्कीम बनाता है, कोई कोर्स चलाता है तो वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं, वे राज्य सरकार की मदद से इस काम को कर सकते हैं। अगर कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐसा पाठ्यक्रम चलाना चाहता है तो UGC की मदद से, उसकी अनुमति से वह उस पाठ्यक्रम को चला सकता है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केन्द्र सरकार स्वयं इस तरह का कोई पाठ्यक्रम नहीं चलाती है लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र की भाषाओं के विकास के लिए कोई विश्वविद्यालय कोई प्रगतिशील योजना लेकर आता है तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

MR. CHAIRMAN: The question is on Bodoland. Many Members have spoken on it. Now, we go to the next question—Question No. 743.

Grants of NGOs

*743. Dr. ALLADI P. RAJKUMAR:†
SHRI YADLAPATI VENKAT RAO:

Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

†The question was actually asked on the flour of the House by Dr. Alladi P. Rajkumar.